GEO IAS

It's about quality

10 July 2024

# GEO Daily

## Daily Current Affairs

## GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | AIR | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

**Date: 10 July 2024**

## Important News Articles

1. भारत, रूस वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाएंगे - द हिंदू
2. केंद्र ने राज्यों के साथ NEP की समीक्षा की, पांच साल की कार्ययोजना तैयार की जाएगी-द हिंदू
3. भारतीय प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार मिला- पीआईबी
4. भारत और UAE के बीच12वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक अबू धाबी में आयोजित हुई- - पीआईबी
5. कोयला मंत्रालय ने फ्लाई ऐश के निपटान और पुनःउपयोग के लिए सक्रिय कदम उठाए- पीआईबी
6. वित्तीय समावेशन-सूचकांक मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 हो गया- द इंडियन एक्सप्रेस
7. न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण माफी किसानों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे - द हिंदू

## Editorials, Gists and Explainers

8. डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (CDCL) - द हिंदू
9. राजस्थान 10 साल के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बनेगा-द हिंदू
10. युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद रूस उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बन गया-इंडियन एक्सप्रेस

## Quick Look

1. KVIC
2. थर्टी मीटर दूरबीन (TMT)
3. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
4. कार्बन क्रेडिट
5. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)

# महत्वपूर्ण समाचार लेख

## सामान्य अध्ययन II

### 1. भारत, रूस वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाएंगे - द हिंदू

**प्रासंगिकता:** भारत से संबंधित और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते।

**प्रीलिम्स टेकअवे**
- भारत - रूस

**समाचार:**
- भारत और रूस वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत हुए

**मुख्य बिंदु:**
- दशक के अंत तक व्यापार और आर्थिक सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण वक्तव्य में नौ मुद्दों पर विचार किया गया
  - गैर-टैरिफ बाधाओं का उन्मूलन
  - राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके द्विपक्षीय निपटान प्रणाली का विकास
  - सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाना और नए संपर्क मार्गों (चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग और उत्तरी समुद्री मार्ग और ईरान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा) का उपयोग करना
  - परमाणु ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश
  - इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
  - निवेश प्रोत्साहन
- इसके अलावा, भारत और रूस ने जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय अनुसंधान, कानूनी मध्यस्थता और दवा प्रमाणन तथा अन्य मुद्दों पर संस्थानों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- भारत और रूस के बीच व्यापार लगभग 65 बिलियन डॉलर का है, जिसका मुख्य कारण यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका और यूरोप द्वारा तेल प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत द्वारा छूट पर रूसी कच्चे तेल के आयात में वृद्धि है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने से भारत के व्यापारिक संबंध उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, जो वर्तमान में केवल अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ है।
- आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना पिछले वार्षिक शिखर सम्मेलनों से अलग था, जहां सैन्य आपूर्ति तथा दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी एजेंडे में शीर्ष पर थे।

### 2. केंद्र ने राज्यों के साथ NEP की समीक्षा की, पांच साल की कार्ययोजना तैयार की जाएगी-द हिंदू

**प्रासंगिकता:** स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

**प्रीलिम्स टेकअवे**
- NEP 2020

**समाचार:**
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए दो दिवसीय बैठक शुरू की।
- मंगलवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

**मुख्य बिंदु:**
- बैठक का मुख्य उद्देश्य NEP, 2020 की समीक्षा करना और इसके कार्यान्वयन तथा मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा, पीएम श्री, पीएम पोषण और उल्लास के साथ इसके संरेखण पर चर्चा करना था। उन्होंने कहा कि बैठक से आने वाले पांच वर्षों के लिए NEP रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी।
- निम्नलिखित विषयों पर चर्चा होगी:
  - पांच वर्षीय कार्य योजना; 100 दिवसीय कार्य योजना;
  - इन्फ्रास्ट्रक्चर और नागरिक कार्यों की प्रगति की स्थिति,
  - समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी और स्मार्ट कक्षाएँ;

- विद्या समीक्षा केन्द्रों और 200 शैक्षिक चैनलों की स्थिति और स्थापना पर चर्चा;
- वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) के आंकड़ों को अंतिम रूप देना; सर्वोत्तम गतिविधियां;

- केरल, तमिलनाडु और ओडिशा जुलाई के मध्य तक NEP के तहत पीएम-श्री योजना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्य अभी भी NEP कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्र के साथ टकराव में हैं।
- "बोर्ड में शामिल होने का निहितार्थ विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाने वाले छात्रों का निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करना और क्रेडिट का सुचारू रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित करना है, जो NEP, 2020 के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के दीर्घकालिक दृष्टिकोणों में से एक है"।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अपने चार वर्षों के कार्यान्वयन में NEP ने काफी प्रगति की है।
  - उन्होंने मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व पर बल दिया और राज्यों से आग्रह किया कि वे सर्वोत्तम गतिविधियों को अपनाने के लिए केन्द्र के साथ मिलकर काम करें।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर ने कहा कि वह पहली बार हिंदी और अंग्रेजी में अपना बी.टेक. कार्यक्रम शुरू करेगा, तथा संबंधित भाषाओं में व्याख्यानों की प्राथमिकता के आधार पर दो अनुभाग निर्धारित किए जाएंगे।
  - "संस्थान ने आगे बताया कि पाठ्यक्रम को एक ही प्रशिक्षक द्वारा दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा ताकि समान कठोरता सुनिश्चित की जा सके"

## 3. भारतीय प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार मिला- पीआईबी

**प्रासंगिकता:** भारत से संबंधित और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते।

**प्रीलिम्स टेकअवे**
- भारत-रूस संबंध
- रूस-यूक्रेन संघर्ष

**समाचार:**
- क्रेमलिन के सेंट एंड्रयू हॉल में एक विशेष समारोह में, रूसी संघ के राष्ट्रपति ने भारत-रूस संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार " **द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल" से सम्मानित** किया।

**मुख्य बिंदु:**
- इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी।
- पुरस्कार स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे भारत की जनता तथा भारत और रूस के बीच मैत्री के पारंपरिक बंधनों को समर्पित किया।
- उन्होंने आगे कहा कि यह मान्यता दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को उजागर करती है।
- इस पुरस्कार की शुरुआत 300 साल पहले हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं।

## 4. भारत और UAE के बीच12वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक अबू धाबी में आयोजित हुई- - पीआईबी

**प्रासंगिकता:** भारत से संबंधित और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते ।

**प्रीलिम्स टेकअवे**
- संयुक्त रक्षा सहयोग समिति

**समाचार:**
- हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की 12वीं बैठक अबू धाबी में आयोजित की गई।
- बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए सहयोग के व्यापक अवसरों पर चर्चा की है।

**मुख्य बिंदु**
- प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा औद्योगिक सहयोग, विषय वस्तु विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, अनुसंधान एवं विकास आदि क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा हुई।
- दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहित क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचार-विमर्श किया तथा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

- एक दूसरे के अनुभव और ज्ञान से लाभ उठाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में यात्राओं के आदान-प्रदान पर भी चर्चा की गई।
- विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण अवसरों के पारस्परिक आदान-प्रदान पर भी सहमति हुई।
- भारत--UAE JDCC की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी।
- तब से अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। 12वीं बैठक ने UAE के साथ भारत के रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और बढ़ाने का अवसर प्रदान किया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई।

# सामान्य अध्ययन III

## 5. कोयला मंत्रालय ने फ्लाई ऐश के निपटान और पुनःउपयोग के लिए सक्रिय कदम उठाए- पीआईबी

**प्रासंगिकता:** इन्फ्रास्ट्रक्चर: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

**प्रीलिम्स टेकअवे**
- SO2 प्रदूषण
- बिजली संयंत्रों

**समाचार:**
- पर्यावरण संरक्षण और संसाधन उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कोयला मंत्रालय (MoC) ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश के उचित निपटान और पुनरुद्देश्यीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
- कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के इस उपोत्पाद का निपटान करके, मंत्रालय एक सतत भविष्य की ओर अग्रसर है, पर्यावरणीय कल्याण को प्राथमिकता दे रहा है तथा एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है।

**मुख्य बिंदु:**
- कोयला दहन के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, कोयला मंत्रालय फ्लाई ऐश के उचित निपटान को बढ़ावा देता है।
- व्यापक शोध और विकास ने खाली जगहों को भरने और निर्माण सामग्री में एक घटक के रूप में फ्लाई ऐश के प्रभावी उपयोग को सक्षम किया है। यह न केवल इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है बल्कि सतत विकास गतिविधियों का भी समर्थन करता है।
- इच्छुक थर्मल पावर प्लांट (TPP) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) को खदानों के आवंटन के लिए आवेदन करते हैं। कुल 13 TPP को 19 खदानें आवंटित की गई हैं।
- यह आवंटन फ्लाई ऐश निपटान से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करता है और कोयला खनन क्षेत्र में सतत गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
- इसके अतिरिक्त, गोर्बीकोल खदान पिट-1 में अब तक लगभग 20.39 लाख टन फ्लाई ऐश का पुन:उपयोग किया जा चुका है।
- प्रभावी प्रबंधन निर्माण गतिविधियों में इसके उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे अपशिष्ट न्यूनतम होता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।
- कोयला मंत्रालय, केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान (CMPDI) के सहयोग से, फ्लाई ऐश बैकफिलिंग गतिविधियों के लिए ताप विद्युत संयंत्रों (TPP) को खदान रिक्तियों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया का प्रबंधन करने हेतु एक केन्द्रीकृत पोर्टल बनाने की प्रक्रिया में है।
- इस पोर्टल का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना है।
- कोयला मंत्रालय फ्लाई ऐश के सुरक्षित संचालन और प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, भारी धातुओं और सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन से जुड़ी संभावित पर्यावरणीय चिंताओं को कम करता है और भारत के लिए स्वच्छ और हरित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सतत गतिविधियों का नवाचार और कार्यान्वयन जारी रखेगा।
- विद्युत संयंत्रों, उद्योगों और नियामक निकायों के साथ सहयोग को बढ़ावा देते हुए, कोयला मंत्रालय का लक्ष्य इष्टतम फ्लाई ऐश प्रबंधन प्राप्त करना है।
- यह सामूहिक प्रयास स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ भविष्य और ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक सतत दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करता है।

## 6. वित्तीय समावेशन-सूचकांक मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 हो गया- द इंडियन एक्सप्रेस

**प्रासंगिकता:** समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दे।

**प्रीलिम्स टेकअवे**
- वित्तीय समावेशन
- जन धन योजना

**समाचार:**
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-सूचकांक), जो देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को दर्शाता है, वर्ष 2023 में 60.1 से बढ़कर वर्ष 2024 में 64.2 पर पहुंच गया।

**मुख्य बिंदु**
- RBI ने कहा कि सूचकांक में सुधार सभी उप-सूचकांकों में देखी गई वृद्धि के कारण हुआ।
- यह सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर सूचना को 0 से 100 के बीच एकल मान में प्रस्तुत करता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है तथा 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
- FI -इंडेक्स में तीन व्यापक पैरामीटर शामिल हैं
  - एक्सेस (सूचकांक में इसका भार 35 प्रतिशत है),
  - उपयोग (भार 45 प्रतिशत), और
  - गुणवत्ता (वजन 20 प्रतिशत)
  - इनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनकी गणना कई संकेतकों के आधार पर की जाती है।
- यह सूचकांक सेवाओं तक पहुंच में आसानी, उपलब्धता और उपयोग, तथा सेवाओं की गुणवत्ता के प्रति अनुक्रियाशील है, जिसमें सभी 97 संकेतक शामिल हैं।
- RBI ने कहा कि FI-इंडेक्स में सुधार मुख्य रूप से उपयोग आयाम के कारण हुआ है, जो वित्तीय समावेशन की गहनता को दर्शाता है।
- सूचकांक की संकल्पना एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है, जिसमें सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल किया गया है।
- FI-सूचकांक का निर्माण किसी भी 'आधार वर्ष' के बिना किया गया है और इस प्रकार यह वित्तीय समावेशन की दिशा में वर्षों से सभी हितधारकों के संचयी प्रयासों को दर्शाता है।
- मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक FI-सूचकांक 53.9 था, जबकि मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए यह 43.4 था।
- FI-इंडेक्स हर साल जुलाई में प्रकाशित किया जाता है।

## 7. न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण माफी किसानों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे - द हिंदू

**प्रासंगिकता:** प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली - उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं, सुधार

**प्रीलिम्स टेकअवे**
- भारतीय कृषि

**समाचार:**
- किसानों को उम्मीद है कि नई सरकार अपने पिछले सभी बजटों से अलग हटकर कुछ नया पेश करेगी।

**मुख्य बिंदु:**
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015 से वर्ष 2022 के बीच 1,00,474 किसानों और कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की।
- यह देश में कृषि संकट का दुखद संकेत है।
- आज देश में किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा C2+50% की दर से वैधानिक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो कि उत्पादन की समग्र लागत का डेढ़ गुना है, जैसा कि एमएस स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी।
  - जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक कृषि संकट का समाधान करना भी असंभव होगा।
- सरकार को बजट के माध्यम से उन कॉरपोरेट्स पर नियंत्रण लाना चाहिए जो इनपुट का उत्पादन कर रहे हैं।

- बजट से इनपुट उत्पादन में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मदद मिलनी चाहिए।
- बजट से तीसरी उम्मीद यह है कि वे देश भर के किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए एकमुश्त पूर्ण ऋण माफी की व्यवस्था करें।
  - जब तक ऐसा नहीं किया जाता, किसानों की आत्महत्या को रोका नहीं जा सकता।
- इस सरकार ने कॉरपोरेट्स का लगभग 16 लाख करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया है।
- ऋण माफी, उत्पादन लागत में कमी लाना तथा C2+50 की दर पर MSP सुनिश्चित करना, ये सभी कार्य एक साथ करने होंगे।
- यदि ऐसा किया जाए तो कृषि क्षेत्र के 70% संकट से निपटा जा सकता है।
- लगातार सूखे, बाढ़, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए एक व्यापक फसल बीमा योजना होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बिल्कुल अलग हो।
- पांचवां बिंदु सिंचाई और बिजली के सवाल पर है। पिछले 10 वर्षों में सिंचाई और बिजली में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में कटौती की गई है।
- देश में कई सिंचाई परियोजनाएं अधूरी हैं। अगर वे पूरी हो जाएं तो जमीन का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के दायरे में आ जाएगा।
- इसलिए बजट में इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रावधान होना चाहिए।
- मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या मात्र 42 रह गई है। सरकार को मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये तथा कार्य दिवसों की संख्या कम से कम 200 करनी होगी।
- सातवां बिन्दु, जो बहुत महत्वपूर्ण है, भूमि का प्रश्न है।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पूर्ण उल्लंघन करते हुए, कॉर्पोरेट घरानों द्वारा कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया जा रहा है।
- भूमि अधिग्रहण केवल तभी किया जाना चाहिए जब सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक हो। क्रांतिकारी भूमि सुधार शुरू किए जाने चाहिए और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए।
- इन सबके लिए संसाधन जुटाने हेतु, केंद्र सरकार को संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर लगाना होगा।
- प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए तथा अप्रत्यक्ष करों में कमी की जानी चाहिए।

# एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

## 8. डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (CDCL) - द हिंदू

**प्रासंगिकता:** आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, जैव-टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

**प्रसंग:**

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर एक अलग कानून की आवश्यकता की जांच के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (CDCL) पर एक समिति का गठन किया।
- CDCL ने इस मुद्दे पर एक वर्ष तक विचार-विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वर्तमान पूर्व-पश्चात ढांचे को एक पूर्व-पूर्व ढांचे के साथ अनुपूरित करने की आवश्यकता है।

| पूर्व-पूर्व रूपरेखा क्या है? | मसौदे का मूल ढांचा क्या है? |
|---|---|
| • प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए प्राथमिक कानून है।<br>○ यह विधेयक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना करता है।<br>○ अन्य सभी न्यायक्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कानून की तरह, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 भी पूर्व-निर्धारित रूपरेखा पर आधारित है।<br>○ इसका अर्थ यह है कि CCI अपनी प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण घटित होने के बाद ही कर सकता है।<br>○ डिजिटल बाजारों के मामले में, CDCL ने प्रत्याशित प्रतिस्पर्धा विनियमन की वकालत की है।<br>○ इसका मतलब यह है कि वे चाहते हैं कि CCI की प्रवर्तन शक्तियों को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि वह डिजिटल उद्यमों को प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लिप्त होने से पहले ही रोक सके।<br>• यूरोपीय संघ एकमात्र ऐसा क्षेत्राधिकार है जहां डिजिटल बाजार अधिनियम के तहत एक व्यापक प्रत्याशित प्रतिस्पर्धा ढांचा वर्तमान में लागू है।<br>• डिजिटल बाजारों की अनूठी विशेषताओं के कारण CDCL इस दृष्टिकोण से सहमत है।<br>• इसलिए, CDCL ने पूर्वव्यापी प्रवर्तन ढांचे के पूरक के रूप में निवारक दायित्वों की वकालत की है। | • मसौदा विधेयक यूरोपीय संघ के डिजिटल बाजार अधिनियम के प्रारूप का अनुसरण करता है।<br>• इसका उद्देश्य सभी डिजिटल उद्यमों को विनियमित करना नहीं है, तथा केवल उन पर ही दायित्व डालता है जो डिजिटल बाजार खंडों में "प्रभावशाली" हैं।<br>• वर्तमान में, मसौदा विधेयक में दस 'प्रमुख डिजिटल सेवाओं' की पहचान की गई है, जैसे ऑनलाइन सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग सेवाएं, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म सेवाएं आदि।<br>• मसौदा विधेयक में डिजिटल उद्यमों के प्रभुत्व की पहचान करने के लिए CCI के लिए कुछ मात्रात्मक मानक निर्धारित किए गए हैं।<br>• ये 'महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति' परीक्षण पर आधारित हैं, जो वित्तीय मापदंडों पर आधारित है, तथा 'महत्वपूर्ण प्रसार' परीक्षण भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या पर आधारित है।<br>• भले ही डिजिटल उद्यम मात्रात्मक मानकों को पूरा नहीं करता हो, फिर भी CCI गुणात्मक मानकों के आधार पर किसी इकाई को "प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम (SSDE)" के रूप में नामित कर सकता है।<br>**प्रतिक्रिया क्या रही?**<br>• मसौदा विधेयक के प्रति सबसे ज़्यादा विरोध की भावना रही है। सबसे पहले, इस बात पर काफ़ी संदेह है कि विनियमन का पूर्व-निर्धारित मॉडल कितना कारगर होगा।<br>• अध्ययनों से यह भी पता चला है कि टाईंग और बंडलिंग तथा डेटा उपयोग पर प्रतिबंध से MSME पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो परिचालन लागत को कम करने तथा ग्राहक पहुंच बढ़ाने के लिए बड़ी तकनीक पर काफी हद तक निर्भर हो गए हैं।<br>• दिलचस्प बात यह है कि भारतीय स्टार्ट-अप्स के एक समूह ने मसौदा विधेयक का समर्थन करते हुए तर्क दिया है कि यह बड़ी टेक कंपनियों की एकाधिकारवादी गतिविधियों के खिलाफ चिंताओं का समाधान करेगा।<br>• हालांकि, उन्होंने वित्तीय और उपयोगकर्ता आधारित सीमाओं में संशोधन की मांग की है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि इससे घरेलू स्टार्ट-अप्स को नियामकीय दायरे में लाया जा सकता है। |

## 9. राजस्थान 10 साल के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बनेगा-द हिंदू

**प्रासंगिकता:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

**समाचार:**

- राजस्थान शीघ्र ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा हेतु कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
- सरकारी नीति के साथ तैयार की जाने वाली इस कार्ययोजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना होगा

| योजना की मुख्य विशेषताएं | सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव |
|---|---|
| **मसौदे के अनुसार:**<br>• **चरण 1 (2025-2027):** यह चरण संस्थागत ढांचे को बढ़ाने, क्षमता निर्माण और कार्य योजना में रेखांकित अंतरिम लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।<br>• **चरण 2 (2028-2030):** यहां लक्ष्य सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की दूसरी दशक की कार्रवाई के अनुरूप सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में 50% की कमी लाना है।<br>• **चरण 3 (2031-2033):** इस चरण का लक्ष्य सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर को 75% तक कम करना है।<br>**सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारण**<br>• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट-2022" से पता चलता है कि भारत में 4.6 ट्रिलियन दुर्घटनाएँ हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 168,000 मौतें हुईं और 400,000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह दुर्घटनाओं में 12% की वृद्धि और मृत्यु दर में 10% की वृद्धि दर्शाता है। योगदान देने वाले कारकों में शामिल हैं:<br>• अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर<br>• यातायात कानूनों का खराब प्रवर्तन<br>• अपर्याप्त इंजीनियरिंग गतिविधियां<br>• सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में सार्वजनिक जागरूकता का अभाव<br>• विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की खराब गुणवत्ता<br>• कानूनी परिणामों का अपर्याप्त निवारक प्रभाव | • सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम तत्काल नुकसान से कहीं अधिक होते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद के 3.18% के बराबर आर्थिक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण मृत्यु और विकलांगता के कारण कार्यबल की उत्पादकता में भी कमी आती है, तथा चिकित्सा व्यय, वाहन मरम्मत और बुनियादी ढांचे को नुकसान के कारण भारी वित्तीय बोझ पड़ता है।<br>**सुशासन**<br>• केरल ने सबरीमाला मंदिर तक जाने वाले चुनौतीपूर्ण पहाड़ी मार्गों सहित अपने सड़कों के नेटवर्क पर शून्य सड़क दुर्घटनाओं के साथ एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों की बदौलत राज्य ने वर्ष 2019-20 से शुरू होने वाले लगातार दो वर्षों तक शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु दर बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है - जो भारत में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।<br>**आवश्यक उपाय**<br>इस समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:<br>• स्मार्ट बुनियादी ढांचे को अपनाना, जैसे:<br>  ○ बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणालियाँ<br>  ○ वास्तविक समय डेटा विश्लेषण<br>• मानवीय त्रुटियों को कम करने और टकराव से बचने में सुधार करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना, जिनमें शामिल हैं:<br>  ○ वाहन-से-वाहन (V2V) संचार<br>  ○ स्वायत्त ड्राइविंग प्रणालियाँ<br>• भारत का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 50% की कमी लाना है। |

It's about quality

## 10. युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद रूस उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बन गया-इंडियन एक्सप्रेस

**प्रासंगिकता:** भारत से संबंधित और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते।

**समाचार:**

- व्यापक पश्चिमी प्रतिबंधों के लागू होने के लगभग ढाई साल बाद, रूस की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है
- इस महीने की शुरुआत में विश्व बैंक ने रूस को "उच्च-मध्यम आय" वाले देश से उन्नत कर "उच्च आय" वाला देश बना दिया, यह दर्जा उसे पिछली बार वर्ष 2014 में मिला था।

**मुख्य बिंदु**

- व्यापार (+6.8%), वित्तीय क्षेत्र (+8.7%), और निर्माण (+6.6%) में वृद्धि से रैंकिंग में सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक (3.6%) और नाममात्र (10.9%) सकल घरेलू उत्पाद दोनों में वृद्धि हुई।

| रूस की रेसिलिएंस | रूसी अर्थव्यवस्था पर अंकुश क्यों कारगर नहीं हुए? |
|---|---|
| • G-7 देशों और यूरोपीय संघ की ओर से व्यापार और वित्तपोषण पर प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप व्यापार चीन, भारत, तुर्की, मध्य एशिया और दक्षिण काकेशस की ओर मुड़ गया, और नए बुनियादी ढांचे और रसद में निवेश कम हो गया।<br>• इस प्रक्रिया के अनुरूप, प्रतिबंध लगाने वाले देशों की मुद्राओं में रूस के बाहरी व्यापार लेनदेन का हिस्सा वर्ष 2021 में लगभग 80% से घटकर वर्ष 2023 में 30% से भी कम हो गया।<br>• सचमुच, चीजें जितनी बेहतर हो सकती थीं, उससे कहीं बेहतर हैं।<br>• रूस का रोजगार बाजार मजबूत है, बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर है, तथा बढ़ती मजदूरी उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे रही है।<br>• वर्ष 2022 में 1.2% के अपेक्षाकृत छोटे संकुचन के बाद, अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करेगी और 3.6% की वृद्धि करेगी।<br>• हालाँकि, मध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाएँ धुंधली बनी हुई हैं।<br>• रूस में व्यापार और परिवार निर्यात पर व्यापक प्रतिबंधों, तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण और निरंतर अंतराल और उच्च व्यापार लागतों के साथ बड़ी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। | • **तेल:** रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध उतने कड़े नहीं हैं जितने वेनेज़ुएला या ईरान पर लगाए गए थे। पश्चिम ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों को डिज़ाइन किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रूस जीवाश्म ईंधन का उत्पादन जारी रखेगा, और तेल की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण उछाल नहीं आएगा। प्रतिबंध और उसके बाद की कीमतों की सीमाएँ शिथिल रूप से डिज़ाइन की गई थीं।<br>  ○ जो तेल पहले यूरोप जाता था, अब अन्यत्र, विशेषकर चीन और भारत में, भेजा जा रहा है।<br>• **निवेश** : रूस के रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है।<br>• उपभोग: निजी उपभोग में जोरदार सुधार हुआ है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 2.9 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है |

**निष्कर्ष:**

- इसके अलावा, वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, और उन्हें पहले ही लागत में शामिल कर लिया गया था।
- मॉस्को में आर्थिक नीति के विशेषज्ञों ने समय के साथ इन उपायों के अनुरूप काम करना सीख लिया है।

GEO IAS It's about quality

# फैक्ट फटाफट

## 1. KVIC

- यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है।
- KVIC को जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, संगठन और कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है।
- KVIC का कार्य उत्पादकों को आपूर्ति के लिए कच्चे माल और उपकरणों का रणनीतिक भंडार बनाना है।
- कच्चे माल को अर्द्ध-तैयार माल के रूप में संसाधित करने के लिए सामान्य सेवा सुविधाएं बनाना तथा KVIC उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाओं का प्रावधान करना।
- खादी और ग्रामोद्योग या हस्तशिल्प के अन्य उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ाना।

## 2. थर्टी मीटर दूरबीन (TMT)

- इसे 30 मीटर व्यास वाले प्राथमिक-दर्पण ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड दूरबीन के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो गहरे अंतरिक्ष में अवलोकन को सक्षम करेगा।
- इसे अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा और भारत के संस्थानों को शामिल करते हुए एक संयुक्त सहयोग के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
- यह विश्व की सबसे उन्नत और सक्षम भू-आधारित ऑप्टिकल, निकट-अवरक्त और मध्य-अवरक्त वेधशाला होगी।
- इसमें परिशुद्ध नियंत्रण, खंडित दर्पण डिजाइन और अनुकूली प्रकाशिकी में नवीनतम नवाचारों को एकीकृत किया जाएगा।
- दूरबीन के केंद्र में खंडित दर्पण है, जो 492 अलग-अलग खंडों से बना है। सटीक रूप से संरेखित, ये खंड 30 मीटर व्यास की एकल परावर्तक सतह के रूप में काम करेंगे

## 3. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास (R&D) संगठन है।
- CSIR की अखिल भारतीय उपस्थिति है और इसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, 3 नवाचार परिसरों और 5 इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क है।
- स्थापना: सितंबर 1942
- CSIR को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रपति: भारत के प्रधानमंत्री (पदेन), उपराष्ट्रपति: केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (पदेन)

## 4. कार्बन क्रेडिट

- कार्बन क्रेडिट (जिसे कार्बन ऑफसेट के नाम से भी जाना जाता है) एक उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजना द्वारा वायुमंडल से ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने या हटाने के लिए दिया जाने वाला क्रेडिट है, जिसका उपयोग सरकार, उद्योग या निजी व्यक्तियों द्वारा अन्यत्र उत्पन्न उत्सर्जन की भरपाई के लिए किया जा सकता है।
- जो कंपनियां आसानी से उत्सर्जन कम नहीं कर सकतीं, वे उच्च वित्तीय लागत पर भी परिचालन कर सकती हैं।
- कार्बन क्रेडिट "कैप-एंड-ट्रेड" मॉडल पर आधारित है जिसका उपयोग 1990 के दशक में सल्फर प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था।

- एक कार्बन क्रेडिट एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, या कुछ बाजारों में, कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य गैसों (CO2-eq) के बराबर होता है।
- ऐसी गतिविधियों के लिए क्रेडिट अक्सर अनौपचारिक तृतीय-पक्ष कंपनियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है और दूसरों को बेच दिया जाता है।
- ऐसे लेन-देन को सत्यनिष्ठा की कमी और दोहरी गणना के लिए चिह्नित किया गया है।

## 5. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP)

- जिसे पहले संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) के रूप में जाना जाता था, क्षय रोग (TB) से निपटने के लिए भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप, 2025 तक भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में टीबी को समाप्त करना है।
- NTEP टीबी का शीघ्र पता लगाने, नियमित और पूर्ण उपचार, रोकथाम रणनीतियों और टीबी देखभाल और नियंत्रण सेवाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- दवा प्रतिरोधी टीबी के मामलों की शीघ्र पहचान के लिए सार्वभौमिक औषधि संवेदनशीलता परीक्षण (UDST)।
- देश भर में सभी टीबी रोगियों के लिए निःशुल्क निदान और उपचार का प्रावधान।

# प्रीलिम्स ट्रैक

**Q1. अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. INSTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान और रूस के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्गों का एक मल्टी-मॉडल नेटवर्क है।
2. INSTC का प्राथमिक उद्देश्य भारत और मध्य एशिया के बीच माल के परिवहन के समय और लागत को कम करना है।
3. अज़रबैजान INSTC का एक प्रमुख सदस्य है, जो अपने क्षेत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग प्रदान करता है।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?**

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

**Q2. भारत में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. शिक्षा को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत एक वस्तु है।
3. समवर्ती सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध विषयों पर केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?**

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

**Q3. पूर्वी यूरोप के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. कार्पेथियन पर्वत रोमानिया और स्लोवाकिया सहित कई पूर्वी यूरोपीय देशों तक फैला हुआ है।
2. डेन्यूब नदी दुनिया की किसी भी अन्य नदी की तुलना में अधिक देशों से होकर बहती है, जिसमें कई पूर्वी यूरोपीय देश भी शामिल हैं।
3. यूक्रेन की सीमा हंगरी और रोमानिया के साथ लगती है लेकिन पोलैंड के साथ नहीं।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?**

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2, और 3

**Q4. भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. यह एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है जो भारत के 90% से अधिक निर्यात को कवर करेगा
2. इसमें चमड़ा, प्रसंस्कृत कृषि और डेयरी उत्पाद, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित लगभग सभी वस्तुएं शामिल हैं।
3. इसमें कृषि क्षेत्र भी शामिल होगा

**उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपर्युक्त सभी

**Q5. थर्मल पावर प्लांट, फ्लाई ऐश और SO2 उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन का एक उपोत्पाद है।
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण गतिविधियों में फ्लाई ऐश के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।
3. ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) अम्लीय वर्षा और श्वसन समस्याओं में योगदान कर सकता है।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?**

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2, और 3

**Q6. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. PMJDY का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।
2. PMJDY के तहत खोले गए खातों को केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए आधार से जोड़ा जा सकता है।
3. PMJDY खाते के छह महीने के संतोषजनक संचालन के बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?**

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2, और 3

**Q7. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP), और भारत सरकार की कृषि नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. किसानों को गारंटीशुदा कीमत सुनिश्चित करने के लिए बुआई के मौसम से पहले कुछ फसलों के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की जाती है।
2. कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) उत्पादन लागत, बाजार मूल्य और मांग-आपूर्ति की स्थिति जैसे कारकों के आधार पर विभिन्न फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है।
3. MSP नीति बिना किसी क्षेत्रीय प्रतिबंध के भारत में उगाई जाने वाली सभी फसलों पर लागू होती है।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?**

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

**Q8. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी।
2. CCI प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार है।
3. CCI के आदेशों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) में अपील की जा सकती है।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?**

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2, और 3

**Q9. अटल भूजल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित टिकाऊ भूजल प्रबंधन की सुविधा के लिए एक योजना है।
2. इसे केंद्र और राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है।

**ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?**

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

**Q10. चीन ने हाल ही में किस देश के साथ 'द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते' पर हस्ताक्षर किए हैं?**

A. सऊदी अरब
B. संयुक्त अरब अमीरात
C. इजराइल
D. रूस

# प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

**उत्तर : 1 विकल्प D सही है**

**व्याख्या :**

- INSTC वास्तव में एक मल्टी-मॉडल नेटवर्क है जिसमें भारत, ईरान, अफगानिस्तान, रूस और अन्य देशों के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग शामिल हैं। **कथन 1 सही है**
- INSTC का प्राथमिक उद्देश्य भारत और मध्य एशिया के बीच माल के परिवहन के समय और लागत को कम करना है, जिससे व्यापार अधिक कुशल और लागत प्रभावी हो सके। **कथन 2 सही है**
- अज़रबैजान INSTC का एक प्रमुख सदस्य है, जो अपने क्षेत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग प्रदान करता है, जो गलियारे के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। **कथन 3 सही है**

**उत्तर : 2 विकल्प B सही है**

**व्याख्या :**

- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। **कथन 1 गलत है**
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता वास्तव में राज्य सूची के अंतर्गत एक वस्तु है। **कथन 2 सही है**
- समवर्ती सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध विषयों पर केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। **कथन 3 सही है**

**उत्तर : 3 विकल्प A सही है**

**व्याख्या:**

- कार्पेथियन पर्वत वास्तव में रोमानिया और स्लोवाकिया सहित कई पूर्वी यूरोपीय देशों तक फैला हुआ है। **कथन 1 सही है**
- डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है, जो कई पूर्वी यूरोपीय देशों सहित दुनिया की किसी भी नदी से सबसे अधिक है। **कथन 2 सही है**
- यूक्रेन की सीमा हंगरी, रोमानिया और पोलैंड के साथ लगती है। इसलिए, **कथन 3 ग़लत है**.

**उत्तर : 4 विकल्प A सही है**

**व्याख्या**

- यह एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है जो भारत के 90% से अधिक निर्यात को कवर करेगा **(कथन 1 सही है)**
- इसमें चमड़ा, प्रसंस्कृत कृषि और डेयरी उत्पाद, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित लगभग सभी वस्तुएं शामिल हैं। **(कथन 2 सही है)**
- इसमें सेवा क्षेत्र भी शामिल होगा **(कथन 3 गलत है)**

**उत्तर : 5 विकल्प D सही है**

**व्याख्या :**

- फ्लाई ऐश वास्तव में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन का एक उपोत्पाद है। **कथन 1 सही है**
- MoEFCC ने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सीमेंट, ईंटों और सड़क निर्माण जैसी निर्माण गतिविधियों में फ्लाई ऐश के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। **कथन 2 सही है**
- ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) अम्लीय वर्षा में योगदान कर सकता है, जो पारिस्थितिक तंत्र और संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। **कथन 3 सही है**

**उत्तर : 6 विकल्प B सही है**

**व्याख्या :**

- PMJDY का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। **कथन 1 सही है**
- PMJDY के तहत खातों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए सिर्फ आधार ही नहीं, बल्कि विभिन्न पहचान दस्तावेजों से भी जोड़ा जा सकता है। **कथन 2 ग़लत है**
- PMJDY खाते के छह महीने के संतोषजनक संचालन के बाद ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है। **कथन 3 सही है**

**उत्तर : 7 विकल्प A सही है**

**व्याख्या :**

- किसानों को गारंटीशुदा कीमत सुनिश्चित करने के लिए बुआई के मौसम से पहले कुछ फसलों के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की जाती है। **कथन 1 सही है**
- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) उत्पादन लागत, बाजार मूल्य और मांग-आपूर्ति की स्थिति जैसे कारकों के आधार पर विभिन्न फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है। **कथन 2 सही है**

- MSP नीति भारत में उगाई जाने वाली सभी फसलों पर लागू नहीं होती है; यह विशिष्ट फसलों के लिए घोषित किया गया है, और कार्यान्वयन सरकारी खरीद और अन्य कारकों के आधार पर क्षेत्रीय रूप से भिन्न हो सकता है। **कथन 3 ग़लत है**

**उत्तर : 8 विकल्प A सही है**

**व्याख्या :**

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी।
- CCI प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार है।
- CCI के आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की जा सकती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) को 2017 में भंग कर दिया गया था और इसके कार्यों को NCLAT में स्थानांतरित कर दिया गया था।

**उत्तर : 9 विकल्प A सही है**

**व्याख्या**

- अटल भूजल योजना रुपये के परिव्यय के साथ स्थायी भूजल प्रबंधन की सुविधा के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 6000 करोड़.
- इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। **अतः, कथन 1 सही है।**
- इस योजना को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 50:50 के आधार पर वित्त पोषित किया जा रहा है। **इसलिए, कथन 2 गलत है।**
- विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण घटक और केंद्रीय सहायता राज्यों को अनुदान के रूप में दी जाएगी।
- उद्देश्य: गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश चिन्हित राज्यों में चुनिंदा जल संकट वाले क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना।
- यह मांग-पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ पंचायत के नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है।

**उत्तर : 10 उत्तर: विकल्पA सही है**

**व्याख्या**

- पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरब ने हाल ही में एक स्थानीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता, तीन साल के लिए वैध है और आपसी सहमति से विस्तार के अधीन है, इसमें 50 बिलियन युआन (6.93 बिलियन डॉलर) या 26 बिलियन सऊदी रियाल की राशि शामिल है। जैसा कि आधिकारिक घोषणा में कहा गया है, इस द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था से दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिलने, स्थानीय मुद्राओं के उपयोग में वृद्धि और व्यापार और निवेश में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

GEO IAS

It's about quality

# ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com